शोध मंथन Vol. XIV No.III July-Sep. 2023 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 8.870 (SJIF)

वैश्वीकरण एवं सहकारिता

प्राप्तिः 24.08.2023
स्वीकृतः 17.09.2023

ममता
शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग
सी०एस०जे०एम० यूनिवर्सिटी, कानपुर
ईमेलः *yadavmamta0905@gmail-com*

70

सारांश

वैश्वीकरण स्थानीय समुदाय के लोगों के हितों की रक्षा करने वाले आंदोलनों को मजबूती प्रदान करता रहा है और जातीयता की प्रसंगिकता को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है वैश्वीकरण एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है। यह उन लोगों को मजबूती प्रदान करता है जो मानते हैं कि वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अर्थात वे एक दूसरे के सहयोग से ही किसी कार्य को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो दुनिया भर में विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं तकनीकी संबंधों में समन्वय बढ़ाने का काम करती है। जो कि एक पैमाने पर संचार परिवहन एवं बुनियादी ढांचे की प्रगति के कारण संभव है। वैश्वीकरण वैश्विक नागरिक समाज का बढ़ता हुआ एक व्यापक दायरा है।

सहकारिता एक विश्वव्यापी आंदोलन है। सहकारिता लोगों का एक ऐसा संगठन है जिसमें लोग मिलजुलकर कार्यों को संपादित करते हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत उस समय हुई जब देश में अकाल की स्थिति थी। किसान गरीबी के दुष्चक्र में फंसे हुए थे । अर्थात् ऐसी स्थिति में भारत जैसे विकासशील देश के लिए सहकारिता का महत्व अधिक है। हमारे देश में 1991 से वैश्वीकरण ने बहुत जोर–शोर से हलचल पैदा की। भारत से पहले विश्व के विभिन्न देशों में वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारवाद जैसे विभिन्न विचारधाराओं का प्रचार–प्रसार हो चुका था। वैश्वीकरण के द्वारा हमारे देश के सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक एवं समस्त पहलुओं में बहुआयामी परिवर्तन देखने को मिले तथा हमारे देश के संबंध विभिन्न देशों के साथ स्थापित किए गए। स्थापित किए गए संबंधों से न सिर्फ भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति हुई बल्कि विभिन्न देशों के साथ आयात–निर्यात के संबंध भी स्थापित करके एक दूसरे पर निर्भरता को बढ़ाते हुए वस्तुओं का आदान–प्रदान किया जाता रहा है। वैश्वीकरण के उद्देश्यों पर नजर डालने से यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव रहित संबंध स्थापित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग, आर्थिक समानता, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, विकास हेतु साझेदारी आदि महत्वपूर्ण पहलुओं पर एक साथ मिलकर बल प्रदान करने का प्रयास किया जाता है।

मुख्य बिंदु

सहकारिता, वैश्वीकरण, सहकारिता का इतिहास, सहयोग, विश्व बंधुत्व की भावना, श्रमिक उदारवाद निजीकरण, प्रशिक्षण लोकतंत्र।

इस लेख का वर्तमान उद्देश्य यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहकारी समितियों की भूमिका का अध्ययन करना बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने के लिए नए–नए आयामों को इसमें शामिल करना है। सहकारी समिति ऐसे संगठनात्मक समूह है। जो लोकतांत्रिक रूप से संगठनों को नियंत्रित करने का काम करती हैं। सहकारी समितियों की अपनी एक अलग कहानी रही है, यह कोई एक नया शब्द नहीं है। बल्कि इसका एक सदियों पुराना इतिहास रहा है। यह अपने परिवेश से सदा ही जुड़ी रही है। सहकारी समितियां अपने सदस्यों को लोकतांत्रिक रूप से भाग लेने, सहयोग व प्रशिक्षण प्रदान करती रही हैं। स्थानीय समुदायों में सहकारी समितियों के महत्व और योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। सहकारी समितियों की अंतरराष्ट्रीयकरण कर देने से सहकारी समितियों के प्रतिस्पध र्ात्मकता और धन व रोजगार पैदा करने की क्षमता बढ़ सकती है। इतना ही नहीं सहकारी समितियों को समय–समय पर अनेकों चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता रहा है। सहकारी समितियों के सामने आने वाली समस्याओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं का विकास करके काम किया जा सकता है। सरकारी समितियों के द्वारा उत्पादन के न्याय संगत टिकाऊ रूपों का प्रतिनिधि ात्व किया जाता रहा है।

सहकारिता और वैश्वीकरण के बीच संबंधों का एक जटिल रूप भी देखने को मिलता है। हालांकि वैश्वीकरण सहकारी समितियों के लिए भी अनेकों अवसर उपलब्ध कराता रहा है। वैश्वीकरण सहकारिता के संबंधों को देखते हुए इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि सहकारी समितियां किस हद तक अपने सिद्धांतों और मूल्यों को पूरा करती है। एक विचारणीय मुद्दा है कि वैश्वीकरण बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देता है। जबकि काफी सीमित हद तक आज भी सहकारी समितियों की पहुंच ऐसे बाजारों तक प्रतिबंधित दिखाई देती है। वैश्वीकरण अधिक से अधिक सहकारी समितियों के लिए एक तार्किक प्रतिक्रिया की तरह प्रतीत होता है। अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सहकारी समितियों को बहुत तेजी से आकर्षित किया जा रहा है। अतः वर्तमान समय का सबसे विचारणीय मुद्दा यह है कि सहकारी समितियों का अंतराष्ट्रीयकरण कैसे किया जा सकता है इस पर गहन विचार की आवश्यकता है।

सहकारी आंदोलनों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ने सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता तथा वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक में एक कृषि ऋण विभाग की स्थापना की। विश्व के प्रत्येक देश में किसी न किसी रूप में सहकारी समितियां अपने–अपने कार्यों का संचालन कर रही हैं। विश्व के 90 देशों में लगभग 700 मिलियन से अधिक लोग सहकारी संस्थाओं की सदस्यता ग्रहण किए हुए हैं। सरकारी समितियों ने आर्थिक मॉडल के रूप में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने में काफी हद तक सफलता दर्ज की है।

प्रतिस्पर्धा भरे इस युग में कृषि सहकारी समितियां नई आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने के लिए एक अच्छी स्थिति में हैं। आईसीए के अनुसार नार्वे में लगभग 75% वन उत्पाद सहकारी समितियों द्वारा संसाधित और विपणन किये जाते हैं। कनाडा की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से कम से कम 8 सहकारी समितियां हैं। जिस प्रकार से सहकारी समितियों को प्रस्तुत करने में

सरकार ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसी प्रकार उनके पास अन्य बातों के अलावा अनुकूल कानूनी और नीतियां तैयार करने की भी आवश्यकता है। जिसमें सहकारी समितियों का विकास हो सके। सरकारी समितियों को संचालित करने में सरकार का बहुत प्रभाव पड़ता है। और यह प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक कुछ भी हो सकता है।

सहकारी समितियों को आमतौर पर प्राथमिक वस्तुओं को संभालने की क्षमता के लिए विकसित किया जाता रहा है। आज श्रमिक, सहकारी समितियों, कार्यस्थल व सामाजिक उद्यम दुनिया भर में पुनर्जीवित हो रहे हैं। एमिलिया रोमाना जो की इटली का एक छोटा सा क्षेत्र है यहां पर सहकारी समितियों के माध्यम से क्षेत्रीय विकास को एक नई दिशा प्रदान करने का काम किया जा रहा है। आज सहकारी समितियों के योगदान व गतिशीलता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वे स्थान जो कारपोरेट प्रणाली नहीं भर पायी हैं। वहां पर सहकारी समितियां उन क्षेत्रों में बखूबी से कार्यों का संचालन करते दिखाई दे रही हैं। सहकारी समितियों ने उन लाखों लोगों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने में सफलता हासिल की है जो या तो बेरोजगार या फिर हासिये पर थे। आज संपूर्ण विश्व की नजरें इसी सहकारी मॉडल पर टिकी हुई हैं।

सहकारी आंदोलन सामाजिक समानता आधारित आंदोलन माना जाता रहा है। सहकारिता अंतरराष्ट्रीय रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरा है। जिसके सहयोग के बिना अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करना असंभव होगा, अतः आज सबसे बड़ी जरूरत लोगों को संगठित होकर आगे बढ़ने की है। जिससे विश्व के बेरोजगारों और हाशिए पर पड़े लोगों को पूर्ण रोजगार प्रदान करने में सहायता मिल सकेगी। संयुक्त राष्ट्र से संबंध रखनेवाला अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आज सहकारिता के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। कृषि सहकारिता के विकास में जैव तकनीकी का प्रयोग बहुत तेजी से किया जा रहा है। यह काम किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि कई व्यक्तियों के समूह के द्वारा संपादित किया जा रहा है। जैसे–जैसे वैश्वीकरण की श्रृंखला अपनी–अपनी पहुंच विभिन्न दिशाओं में फैला रही है, इसमें अनेक प्रकार की विविधताएं भी देखने को मिल रही हैं।

विश्व में सफल सरकारी प्रयोगों में स्पेन के बास्क प्रदेश में मोंड्रैगन परिवार का उद्यम है। वर्ष 1956 में इसकी शुरुआत हुई। लगभग 1964 में एक शिक्षा परियोजना से स्नातकों के लिए रोजगार देने के उद्देश्य से पैराफिन हीटर बनाने वाली छोटी कार्यशाला शुरू की गई थी। वर्तमान समय में टर्न ओवर के मामले में यह सातवीं सबसे बड़ी स्पेनिश कंपनी है और बास्क प्रदेश में अग्रणी व्यापार समूह है। अतः मोड्रैगन की यह कहानी सहकारी मार्ग को प्रशस्त करने व प्रगतिशील बनाने में नवाचार सिद्ध हो सकती है। जो न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों को सीधे तरीके से लाभान्वित कर सकती है। वैश्वीकरण के द्वारा दुनिया भर में लोगों के मध्य अंतरसंबंध देखने को मिले हैं वैयाक्तिक सहयोग को बढ़ाने में भी वैश्वीकरण एवं सहकारिता दोनों ही सफल दिखाई दे रहे हैं।

हमारे देश में सहकारिता एकमात्र ऐसा तरीका है। जिसके माध्यम से किसान अपने कर्ज के बोझ से उभर सकते हैं। हमारे लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि वर्तमान समय में हमारी सरकारें पूरी तरह से सहकारिता को जीवंतता प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाती नजर आ रही हैं।

संदर्भ

1. Wahl, Cristian Daniel. (2018). The Cooperative Path. March.
2. Curl, John. Tha Cooperative Movement in Century 21. Pg. 24.
3. Gray, Thomas W. (2001). Agricultural cooperatives And Dilemma of Survival. June. Pg. **90.**
4. Kathar, Ganesh N. (2016). Globalization and Its Impact on Cooperative Sector In India.
5. Buchain, Nancy., Grimilda., Wilson, Rick., Brewer. (2009). Globalization and Human Cooperation. 17 march. Pg. **1.**
6. Brettos, Ignacio., Marcello, Carmen. (2009). Revisiting Globalization challenges and Opportunities in the development of Cooperatives (Aug-201). Pg. **1.**
7. Reed, Darryle., Maclod, Gerg., Ruggeri, Andress. (2009). Cooperative in a Global Economy. A challenges of cooperation across Borders. Jan. Pg. **11.**